



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

केंद्र के साथ
अब मिलेगी राज्य
की भी सब्सिडी



अतिशेष बिजली
हिस्सों को
बेच कर होगी
अतिरिक्त कमाई

उपभोक्ता से
बनें ऊर्जादाता

पीएम
सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना



PDCL

इबल
सब्सिडी

मासिक बिजली बिल से भी कम EMI में*

लगाएं रूफटॉप सोलर प्लांट

1kW मात्र ₹15,000 में ₹170 (मासिक EMI)	2kW मात्र ₹30,000 में ₹341 (मासिक EMI)
--	--



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं

<https://pmsuryaghar.gov.in/>

*बैंक द्वारा 6.5% ध्याज दर पर आसान किरतों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा (EMI) उपलब्ध

हमारा संकेतः हाफ बिजली से मुफ्त बिजली

आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण

पाकिस्तान अब क्या करेगा ? चीन-तुर्किये के ड्रोन की खैर नहीं...

नयी दिल्ली, 16 जुलाई 2025(ए)। भारतीय सेना ने लद्दाख में आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य यह देखना था कि यह सिस्टम ऊंचाई पर कैसे काम करता है। डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से भारतीय सेना ने यह परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बहुत तेजी से चलने वाले लक्ष्य विमानों को सीधे निशाना बनाया।

आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी और चौथी रेंजिमेंट

आकाश प्राइम सिस्टम भारतीय सेना में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी और चौथी रेंजिमेंट होगी। डिफेंस अधिकारियों के अनुसार, इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी विमानों और तुर्किये के ड्रोन का उपयोग करके पाकिस्तान सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों को विफल करने में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।



परीक्षण में निशाना सीधे टारगेट पर लगा

आर्मी एयर डिफेंस ने डीआरडीओ के साथ मिलकर यह परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ही इस सिस्टम को बनाया है। ऐसे में मिसाइल का प्रदर्शन देखना महत्वपूर्ण था।

मिसाइलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सीधे निशाने पर लगीं। एक डिफेंस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में इस सिस्टम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोकने में मदद की।

आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम क्या है ?

आकाश प्राइम एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह दुश्मन के विमानों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। यह भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा। लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले

क्षेत्रों में यह सिस्टम बहुत उपयोगी साबित होगा। कुल मिलाकर इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं।

जब आसमान में गरजेगा, पाकिस्तान-चीन कांपेंगे! भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टरों मिलेगी ?

भारत अपनी सेना को और भी शक्तिशाली बनाने जा रहा है। अगले हफ्ते भारत को 6एएच - 64ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों में से पहले तीन मिल जाएंगे। यह भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। 2020 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत ये हेलीकॉप्टर भारत को मिल रहे हैं। इससे भारत की पश्चिमी सीमा और भी सुरक्षित हो जाएगी। ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारत की हवाई ताकत को बढ़ाएंगे। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनसे दुश्मन पर हमला करना आसान होगा।



मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले

नयी दिल्ली, 16 जुलाई 2025(ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाले तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेंवेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को 2025-26 से शुरू कर छह वर्षों के लिए मंजूरी दी है। इसका टारगेट 100 कृषि जिलों का विकास करना है। यह योजना नीति आयोग के 'आकांक्षी जिलों' कार्यक्रम से प्रेरित है, लेकिन यह खासतौर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। योजना का मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ कृषि ऑप्शन को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना शामिल है। इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के कोऑर्डिनेशन के जरिए

लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकारों की योजनाएं और निजी क्षेत्र की साझेदारी भी शामिल होगी। 100 जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल साइकिल और कम लोन डिस्ट्रिब्यूशन जैसे तीन प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाएगा। हर राज्य से कम से कम एक जिला शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को रेंवेबल एनर्जी क्षेत्र में निवेश के लिए मौजूदा सीमा से ऊपर जाकर 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी है। यह निवेश एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा, ताकि 2032 तक 60 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल की जा सके। एनएलसीआईएल को भी 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की विशेष छूट दी गई है, जो वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड के जरिए रेंवेबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाएगी। इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।



छत्तीसगढ़
सहस्राक्षर अभियान

"विमोचन"

छत्तीसगढ़ अंजोर

विजन@2047

मुख्य अतिथि

श्री विष्णु देव साय

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं पर
केंद्रित रूपरेखा

विजन डॉक्यूमेंट

राज्य के अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक
लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रोडमैप

दिनांक : 17 जुलाई 2025, गुरुवार
समय : सायं 05:00 बजे
स्थान : होटल मेफेयर, नवा रायपुर

सुधर डहर, उज्जर भविस



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



Chhattisgarh CMO
DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

संपादकीय

ट्रंप की प्रतिक्रिया

फिलिस्तीन और पश्चिम एशिया के लिए कोई न्याय की बात करे यह बात नेतन्याहु और ट्रंप को हजम नहीं होती। यही कारण है कि जब ब्रिक्स देशों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, अस्थिरता और गाजा के खिलाफ इस्त्रइली हमलों और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की तो ट्रंप तिलमिला उठे। जब ट्रंप अपने देश में यहूदी विरोध के बहाने अपने ही विविद्यालयों पर तमाम पाबंदियां लगा सकते हैं तो ब्रिक्स देशों की यह हरकत कैसे बर्दाश्त करते। फलस्वरूप उन्होंने इन देशों पर ही अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी तक दे डाली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणा-पत्र ट्रंप के तिलमिलाने का कारण साबित हुआ। घोषणा-पत्र में कही गई हर बात ट्रंप और नेतन्याहु का मुंह ही नहीं चिढ़ाती, बल्कि इसकी भी झलक दिखाती है कि बदलती दुनिया क्या चाहती है। घोषणा-पत्र में ब्रिक्स देशों ने दोहराया कि इस्त्रइल-फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत और स्थायी समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है।यह फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों की पूर्ति पर निर्भर करता है, जिसमें आत्मनिर्णय और वापसी के अधिकार शामिल हैं। ब्रिक्स ने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन करने का आह्वान किया है,और मानवीय सहायता के राजनीतिकरण और सैन्यीकरण के प्रयासों की निंदा की। घोषणा-पत्र सामने आते ही ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली और कहा कि इसका कोई अपवाद नहीं होगा।लगता है कि ट्रंप ने अपवाद न होने वाली बात कह कर भारत को भी अपना रुख कड़ा करने का इशारा दे दिया है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक दबाव का निर्थक साधन बताया। लेकिन ट्रंप भारत के साथ एक बड़े व्यापार समझौते का जो इशारा देते रहे हैं,लगता है वह उलझ सकता है। अभी तक तो भारत इस्त्रइल विरोधी किसी भी मुद्दामें शामिल होने से किनारा करने की नीति पर चलता रहा है, लेकिन लगता है कि ब्रिक्स घोषणा-पत्र भारत की मजबूरी बन गया है। ब्रिक्स के मूल सदस्यों में शामिल रूस और चीन के तो अमेरिका के दबाव में आने की बात सोचना भी संभव नहीं है, लेकिन भारत, मिस्र, इथियोपिया,इंडोनेशिया,ईरान,सऊदी अरब और संयुक्त अरब एमीरात के लिए दिक्रतें बढ़ने वाली हैं।

नीति आयोग की मानव

पूँजी से संबंधित क्रांति

भारत जैसे विशाल और वैविध्यपूर्ण देश में प्रगति का वास्तविक पैमाना केवल जीडीपी के आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि वह देश अपनी जनता का कितने बेहतर ढंग से पोषण करता है। मानव पूँजी-हमारी कौशल,स्वास्थ्य और उत्पादकता-केवल एक आर्थिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यता भी है। पिछले दस वर्षों में, भारत के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक-नीति आयोग के नेतृत्व में एक शांत लेकिन प्रभावशाली क्रांति ने आकार लिया है, जिसने देश द्वारा अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, यानी अपने नागरिकों, में निवेश करने के तरीके को नए आकार में ढाला है।एक ऐसे देश में जहाँ 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र वाले लोगों की है, तो वह जनसांख्यिकीय लाभान्श बेहद दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। लेकिन इस युवा आबादी का विशाल आकार अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। प्रमुख चुनौती इस युवा ऊर्जा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास की शक्ति में रूपांतरित करना है। यहीं पर नीति आयोग एक दूरदर्शी उद्देश्य के रूप में उभरा है-जो न केवल आज की प्रगति,बल्कि भविष्य की समृद्धि का भी रोडमैप तैयार कर रहा है। पिछले एक दशक में,नीति आयोग एक थिंक टैंक से एक सुधारवादी साधन और कार्य-न्ययन भागीदार के रूप में विकसित हुआ है, जो आँकड़ों, सहयोग और मानव-केंद्रित डिजाइन द्वारा समर्थित सांख्यिक विचारों के लिए जाना जाता है। इसने नीति-निर्माण को एक शीर्ष-स्तरीय प्रक्रिया से आलोचनात्मक चिंतन, लचीलेपन और व्यावसायिक एकीकरण का रुख करते हुए एक नए युग का सूत्रपात किया। इसने प्राथमिक बाल्यवास्थ शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और विषयों के बीच निर्बाध परिवर्तन पर जोर दिया। इसने देश भर में मौजूद 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब्स में नवाचार को समाहित करते हुए अटल नवाचार मिशन जैसी पहलों के माध्यम से जवाबदेही और कल्पनाशीलता दोनों को सुनिश्चित किया।भारत के युवाओं को 21वीं सदी के लिए कुशल बनाना इसके मिशन का एक और आधार रहा है। कौशल भारत मिशन को समर्थन देने से लेकर आकाशी जिला कार्यक्रम के माध्यम से वींचित जिलों के महत्व पूर्ण भाग तक व्यावसायिक कार्यक्रमों की पहुँच सुनिश्चित करने तक, नीति आयोग ने कक्षा और करियर के बीच की खाई को पाटने में मदद की है।

-इंद्रजीत सिंह-



प्रियंका सौरभ
आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)

अश्लीलता की रील
संस्कृति पर एक सवाल

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ स्त्रीन पर दिखना असल में जीने से ज्यादा जरूरी हो गया है। जहां ज़िंदगी कैमरे के फ्रेम में सिमट गई है, और ईंसान का मूल्य उसके लाइक, फॉलोवर और व्यूज से तय होता है। इसी डिजिटल होड़ में स्त्रियों की अभिव्यक्ति भी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई है—जहाँ रील

बनाना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन रील के बहाने स्त्री की गरिमा और उसकी सामाजिक छवि का बेशर्म चीरहरण किया जा रहा है। जिम,मॉल,सड़क, बाथरूम और बेडरूम-हर कोना अब कंटेंट स्टूडियो बन चुका है। कुछ लड़कियाँ सोशल मीडिया पर जिस तरह की अश्लील और भद्दी रीलस बना रही हैं, वह केवल खुद की नहीं, समूची नारी जाति की गरिमा पर धब्बा बन रही है। क्या आपको सच में लगता है कि महज वायरल हो जाने से कोई लोकतंत्र बनता है? एक औरत के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान और विवेक होता है। आज जो लड़कियाँ एक्सरसाइज के नाम पर ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि देखना भी शर्मिंदगी पैदा करे, वे

शायद यह नहीं जानतीं कि वे नारी मुक्ति नहीं बल्कि नारी बाजारीकरण का प्रचार कर रही हैं। शरीर दिखाकर पहचान बनाना कोई गर्व की बात नहीं। अगर रीलस ही बनानी हैं,तो क्यों न ऐसी रील बनाओ जिसमें आपकी कला, मेहनत, सोच और संवेदना झलके? आज हर तीसरी रील में पिछड़ा फ्रेम के बीच में है, कैमरा कमर पर जुम करता है, और कैप्शन होता है — क्लासी एंड सेक्सी! क्या यही स्त्री की परिभाषा बनती जा रही है? स्त्री आंदोलन कभी इस उद्देश्य से नहीं चला था। हमने शिक्षा, समानता, आजादी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ी थी, न कि मंच पर खड़े होकर अंग प्रदर्शन की। जो लोग कहते हैं, ये स्त्रियों की आजादी है,उन्से पूछिए-क्या

शरीर को उत्पाद बनाना आजादी है या आधुनिक गुलामी? और यह दोष सिर्फ उन लड़कियों का नहीं है जो ऐसी रीलस बनाती हैं। यह समाज का भी अपराध है—खासतौर पर पुरुषों का। यही पुरुष ऐसी वीडियो पर मिलियन-मिलियन व्यूज देते हैं, लाइक टोकते हैं, फिर कमेंट में नैतिकता का भाषण भी पेलते हैं। एक ही वीडियो में पुरुष की आँखें भी डोलती हैं और उंगलियाँ भी नैतिकता टाड़प करती हैं। यह दोगलापन बंद होना चाहिए।सोचिए, क्या होगा जब कोई छोटी बच्ची यह सब देखकर बड़ेगी? जब वह देखेगी कि ज्यादा अंग दिखाते वाली को ज्यादा लाइक मिलते हैं, तो वह किस दिशा में जाएगी? यह रील संस्कृति, स्त्रीत्व को छीनने की

चुपचाप होती साजिश है। डिजिटल ग्लैमर को इस दौड़ में हम स्त्री को फिर से उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहाँ उसे सिर्फ देखे जाने की वस्तु बना दिया गया था। आजादी की सही परिभाषा वो होती है जिसमें स्त्री खुद के लिए जीती है,न कि समाज के क्लिकबाजी वाले बाजार के लिए। एक लड़की सुंदर हो सकती है,फैशनेबल भी, लेकिन क्या जरूरी है कि वह हर बार अपनी देह को ही सेल करे? क्या सोच, क्या विचार, क्या चरित्र, क्या संघर्ष—ये सब सिर्फ उपन्यासों की बातें रह गई हैं? दूसरी तरफ, जिन प्लेटफॉर्मों को समाजिक सुधार का औजार माना गया था—जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक—उन्हें हमने डिजिटल कोय बना डाला है। यह केवल

सरकार की असफलता नहीं है, बल्कि हम सब की चुप्पी का परिणाम है। यह लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं,बल्कि हर उस ईंसान की होनी चाहिए जो एक स्वस्थ, गरिमामय,और नैतिक समाज की कल्पना करता है। जो चाहता है कि उसकी बेटी, बहन, दोस्त या पत्नी डिजिटल दुनिया में अपने टैलेंट से पहचानी जाए, न कि अपनी कमर के घुमाव से।अब समय आ गया है कि स्त्रियाँ खुद आगे बढ़कर कहें—बस बहुत हुआ। रीलस बनानी हैं, बनाओ, लेकिन सोच से बनाओ। डांस करो, पर आत्मा से—नॉट कैमरे की भूख से।हंसाओ, सुनाओ,सिखाओ,जोड़ो—वहीं की सिर्फ आकर्षण नहीं, प्रेरणा होती है। और पुरुषों से भी यही कहना है—

अब अपने क्लिक से समाज को मत चलाओ। अगर अश्लीलता बंद करनी है, तो उसे देखना बंद करो।रीलस वायरल तब होती हैं जब उन्हें देखे जाने वाले आँख मूंद लेते हैं और दिल खोल देते हैं। एक बात और—जो लड़कियाँ यह सोचती हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वे ये समझें कि पसंद और उपभोग में फर्क होता है। एक को देख कर सम्मान मिलता है, दूसरे को देख कर हव्स जागती हैं। आप खुद तय करें, आप कौन सी नज़रों में आना चाहती हैं? शायद अब वक्त है एक नई डिजिटल क्रांति का,जहाँ स्त्री के हथ में मोबाइल हो-पर कैमरे के सामने न शरीर,बल्कि विचार हों। रील में न खोओ बहना, सोच को आवाज दो,जो तुम हो भीतर से, वहीं असली साज्द दो बदन की नहीं,बुद्धि की बनाओ पहचान,यही है स्त्री की सबसे ऊँची उड़ान!

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

अभिव्यक्ति की पीठ पर खड़ी पत्रकारिता

और प्रतिष्ठ के मौन में थरथराता न्याय



अभिमनोज
तिलहरी,जबलपुर -482021
मध्यप्रदेश

जब पत्रकार अपने शब्दों से सत्ता की चुपियों को तोड़ता है, तो वह केवल सूचनाएँ नहीं बाँटता, वह सत्य की संभावनाएँ खोलता है। पर यही पत्रकार,जब डिजिटल माध्यम के अनियंत्रित तूफान में खड़ा होता है, तो उसके शब्द तलवार बन सकते हैं—जिसका एक छोर जनहित की रक्षा करता है,और दूसरा अनजाने में किसी की प्रतिष्ठा को लहलुहान कर सकता है। यही वह गहरी रेखा है,जहाँ भारत का संवैधानिक अधिकार—अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता—और एक नागरिक का मौलिक सम्मान—प्रतिष्ठा की रक्षा—एक दूसरे से टकराने लगते हैं। डिजिटल पत्रकारिता,जो आरंभ में स्वराज और स्वतंत्र संवाद की भूमि थी,अब एक ऐसा मंच बन गई है, जहाँ शब्दों की रफ्तार सच्चाई से तेज और जिम्मेदारी से हल्की हो चली है। पारंपरिक मीडिया के पास संपादकीय अनुशासन, कानूनी समीक्षा और नैतिक मर्यादाएँ होती थीं; परंतु अब एक स्वतंत्र यूट्यूबर पत्रकार या ब्लॉग लेखक महज एक क्लिक में करोड़ों लोगों तक पहुँच सकता है। पर इसी शक्ति के साथ, उसकी एक असावधान अभिव्यक्ति समाज, कानून और व्यक्ति तीनों को प्रभावित कर सकती है।

शब्दों की अदालत: जब

पत्रकारिता न्याय के



विजय गर्ग
चांद मलोेट
पंजाब

शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कहा गया है। यह व्यक्ति के ज्ञान, विवेक, सुजनत्वकता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम रही है। लेकिन आज की तारीख में यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है। शिक्षा अब एक अंक-उद्योग में तब्दील हो चुकी है, जहाँ ज्ञान की बजाय नंबर ही सफलता का पर्याय बन गए हैं। अब यह न तो चरित्र निर्माण का साधन रही, न ही सामाजिक चेतना का उपकरण। यह सूनिर्वाहकों और शिक्षकों को अंक दौड़ की एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में धकेलने वाला शोषण तंत्र बन गई है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो

कटघरे में होती है...

पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है, और उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका शब्द है। पर आज वही शब्द कई बार एफआईआर बन रहा है, और वही आवाज अदालतों में अपराध के कटघरे में खड़ी हो रही है। विशेषतः डिजिटल पत्रकारिता के इस नए युग में, जहाँ कोई स्वतंत्र पत्रकार अपने मोबाइल कैमरे या यूट्यूब चैनल के जरिये सत्ताधारी वर्ग को कटघरे में खड़ा कर सकता है, वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के कानून के बीच का द्वंद्व एक तीखा और जटिल रूप ले चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है,किंतु अनुच्छेद 19(2) इस स्वतंत्रता पर कुछ यथोचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है—जिनमें मानहानि प्रमुख है। यही वह संवैधानिक द्वंद्व है जहाँ पत्रकार का कलम और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एक-दूसरे के आमने-सामने आ खड़े होते हैं। नए अपराधिक कानून—भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)—में मानहानि को दंडनीय अपराध बनाए रखा गया है। बीएनएस की धारा 356 (पूर्ववत आईपीसी की धारा 499) मानहानि की परिभाषा देती है और धारा 357 (पूर्व आईपीसी की धारा 500) इसके लिए दंड का प्रावधान करती है—जिसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्ष की कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। साथ ही, आईपीसी की धारा 500 (अब बीएनएस की धारा 357) लंबे समय से यह स्थापित करती आई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की मानहानि करता है, तो वह एक आपराधिक अपराध होगा, और इसमें अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि डिजिटल पत्रकारिता के किसी कृत्य में



जानबूझकर झूठी सूचना फैलाने का उद्देश्य हो, तो बीएनएस की धारा 197(1) (पूर्व आईपीसी की धारा 505) भी लागू हो सकती है, जो सार्वजनिक शांति भंग करने वाली झूठी या भ्रामक खबरों को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यहीं से प्रश्न उठता है—जब एक डिजिटल पत्रकार किसी मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी के भ्रष्टाचार का खुलासा करता है, और उसके तुरंत बाद उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या यह न्याय का अनुपालन है, या सत्य को दबाने का रणनीतिक प्रयास? सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016) में इस प्रश्न का उत्तर दिया था। न्यायालय ने कहा, लोकतंत्र केवल राजनीतिक संरचना नहीं, विचारों का क्षेत्र है, और आलोचना उसकी प्राणवायु है। केवल इसलिए कि कोई सार्वजनिक व्यक्ति असहज होता है,उसे मानहानि का मामला बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।- परंतु जमीनी हकीकत इस निर्णय के प्रतिक्लृप्त ही दिखाई देती है।

2021 में मध्यप्रदेश में एक स्वतंत्र पत्रकार ने फेसबुक पर एक मंत्री के जमीन विवाद की रिपोर्ट साझा की, और तुरन्त उसके विरुद्ध मानहानि की एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक उसी वर्ष, उत्तर प्रदेश में पत्रकार मनोज सिंह ने कोविड काल में अक्सिजन की भारी कमी पर रिपोर्टिंग की,और उन पर न केवल मानहानि, बल्कि बीएनस की धारा 150 (पूर्व आईपीसी की धारा 124, राजद्रोह) भी लगा दी गई। यह घटना स्पष्ट करती है कि कुछ शक्तिशाली संस्थाएँ पत्रकारिता को चुनौती नहीं, अपराध मानने लगी हैं। इस विधिक दमन की एक खतरनाक प्रवृति है—एसएलएपीपी यानी ऐसा मुकदमा जो पत्रकारों को चुप कराने और डराने के लिए दायर किया जाता है। भारत में इसके उदाहरण तेजी से बढ़ रहे हैं, जहाँ बड़े कारोबारी समूह, राजनेता और अधिकारी जानबूझकर मानहानि के मुकदमे का उपयोग कर रहे हैं ताकि पत्रकार दबाव में आकर रिपोर्टिंग से पीछे हट जाए। इन मामलों में मानहानि एक औजार बन जाती है—अभिव्यक्ति को डराने का,न कि प्रतिष्ठा की रक्षा का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल उसके अस्तित्व की बात नहीं, बल्कि उसकी निर्भीकता की भी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन इस संवाद में केवल पत्रकारों को पीड़ित मान लेना भी न्याय नहीं होगा। डिजिटल पत्रकारिता में तथ्य-जांच, द्वितीय पक्ष की राय और भाषा की मर्यादा अक्सर उपेक्षित होती है। कई यूट्यूब पत्रकार रिपोर्ट नहीं, निर्णय सुना देते हैं। अगर कोई पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग में किसी को भ्रष्ट, अपराधी या हत्यारा घोषित करता है—बिना अदालत के निर्णय या स्पष्ट प्रमाण के—तो यह केवल मानहानि नहीं,

परीक्षा प्रणाली या सामाजिक भ्रमजाल ?



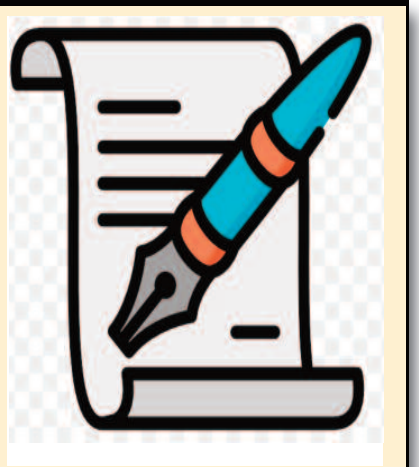
सिबीएसई की 10वीं की परीक्षा में इस बार 45,516 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 1.92 प्रतिशत है। वहीं 1,99,944 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए, जो 8.43 प्रतिशत के करीब है। यह कोई अपवाद नहीं है हर साल यह आंकड़ा और ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इन अंकों की असलियत जानने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों की कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो व्यवस्था मौन हो जाती है। यह एक सांजिन खड़ा किया गया भ्रमजाल है, जो शिक्षा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बजाय एक कुत्रिम दौड़ में तब्दील कर रहा है। शिक्षा के इस व्यवसायीकरण की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस ढांचे को देखें जिसमें यह सब संघीलाइत हो रहा है। 2019 में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कुल 22,030 स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े में केवल 1,138



केंद्रीय विद्यालय, 2,727 सरकारी स्कूल, 598 नवोदय विद्यालय और 14 तिब्बती स्कूल शामिल हैं,जबकि शेष 17,553 निजी स्कूल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा निजीकरण के दबाव में है,जहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि परिणामों की संख्या मायने रखती है और जब यही %अंकवीर छत्र राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी,जेईई या नीट में पहुंचते हैं,तो उनकी वास्तविक योग्यता सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा 2019 में लगभग 11.35 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 11,474 छात्र ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सके। यही हाल साल 2024 का रहा। इस वर्ष लगभग 13.4 लाख छात्रों में से सिर्फ 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचे। यानि बोर्ड परीक्षा के हाई स्कोरर प्रीलिम्स की पहली कसौटी पर ही फेल हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले ऊंचे अंक असल में बौद्धिक क्षमता या विषय की समझ का पैमाना नहीं हैं। यह मूल्यांकन प्रणाली रटत विद्या तपश्चुदा उत्तरों और सजावटी भाषा पर आधारित है,जिसमें मौलिक सोच और विश्लेषण की कोई जगह नहीं।यह समस्या केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है,बल्कि यह

मानसिकता पूरे उत्तर भारत के शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है। स्कूलों में अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे परिणामों के जरिए स्कूल का नाम रोशन करना बन गया है। इसके उलट, दक्षिण भारत की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर है। वहां के माता- पिता शिक्षा को केवल अंक पाने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और कौशल निर्माण के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्र राष्ट्रीय परीक्षाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वहां की शिक्षा प्रणाली में केवल परीक्षाफल नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहारिकता और नवाचार को भी महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर स्कूलों में शिक्षण अब गाइडबुक,मॉडल पेपर और स्मार्ट आंसर पर आधारित हो गया है। शिक्षक भी केवल परिणाम उन्मुख होकर पढ़ाते हैं,क्योंकि उनके मूल्यांकन का आधार भी अब बच्चों के अंक बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर की होड़ में बच्चों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृति,हीन भावना और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक दौड़ बन गई है, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता माना जाता है।

अब अपने क्लिक से समाज को मत चलाओ। अगर अश्लीलता बंद करनी है, तो उसे देखना बंद करो।रीलस वायरल तब होती हैं जब उन्हें देखे जाने वाले आँख मूंद लेते हैं और दिल खोल देते हैं। एक बात और—जो लड़कियाँ यह सोचती हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वे ये समझें कि पसंद और उपभोग में फर्क होता है। एक को देख कर सम्मान मिलता है, दूसरे को देख कर हव्स जागती हैं। आप खुद तय करें, आप कौन सी नज़रों में आना चाहती हैं? शायद अब वक्त है एक नई डिजिटल क्रांति का,जहाँ स्त्री के हथ में मोबाइल हो-पर कैमरे के सामने न शरीर,बल्कि विचार हों। रील में न खोओ बहना, सोच को आवाज दो,जो तुम हो भीतर से, वहीं असली साज्द दो बदन की नहीं,बुद्धि की बनाओ पहचान,यही है स्त्री की सबसे ऊँची उड़ान!



कविता
कौन कितना है...

घटती-घटना
राजेन्द्र लहरी
पामगढ़
छत्तीसगढ़

नहीं जाना है उस राह में जिससे नहीं है मेरा कोई वास्ता, ला देते हैं रोड़े राहों में रोक लेते प्रगति वाला रास्ता, मस्तिष्क को गिस्वी रख कर हर पल उलझे रहते हैं, हवाबाजी की बातें बता खुद को ज्यादा सुलझे कहते हैं, राहें आदमी को कहीं नहीं ले जाती लोग खुद ही राह बनाते हैं, सफल हो जाने वाला सबको एक अलग मॉजिल दिखाते हैं, चालाक व्यक्ति एक ऐसा वातावरण बनाना चाहता है मकड़ी की जालों में फंसे हुए कीटों की तरह कसमसा कर बैठे लोगों को उलझाकर एक अलग राह दिखा बैठे बैठे ताउम्र खाना चाहते हैं, सब लोग हैं एक दूसरे को उलझाने में, खुद को समझदार दिखाने में, लेकिन समझदार वही है जो उनकी सहमति से उन्हें लुटे, विनम्रता से सब समर्पित कर कहे अभी तक हमारे भाग थे फूटें, आज हिदायतें लगाने लगा है बकबक, पता नहीं चलता है कौन कितना अहमक।

विद्यालयों में 6 से 12 अगस्त तक मनाया जाएगा संस्कृत सप्ताह

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में इस वर्ष भी श्रावण पूर्णिमा (रक्षाबंधन) के तीन दिन पूर्व एवं तीन दिन बाद अर्थात 06 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्कृत सप्ताह के आयोजन संबंधी निर्देश सचिव,छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रायपुर द्वारा जारी किए गए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार इस अवधि में विद्यालयों में निबंध लेखन,वाद-विवाद, संस्कृत नाटक, कहानी लेखन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही संस्कृत आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विद्वानों की संगोष्ठी,साहित्य प्रदर्शनी,भाषण,परिचर्चा एवं संस्कृत गीत आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि अनुसार कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करें एवं संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ऐसे बालक-बालिकाएं जिन्होंने बहादुरी,खेल, सामाजिक सेवा और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण,कला और संस्कृति एवं नवाचार के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उपलब्धि प्राप्त की है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाना है। जिसके लिए पात्र बालक एवं बालिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु ऑनलाइन पोर्टल <https://awards.gov.in> पर 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक भारतीय नागरिक हो, प्राप्त उपलब्धि आवेदन करने की अंतिम तिथि से दो वर्ष के भीतर होनी चाहिए, आवेदक को उक्त समान श्रेणी में पूर्व में पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ हो। उन्होंने बताया कि आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मो.न. 7000448404 पर संपर्क किया जा सकता है।

भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई

बलरामपुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि भारतीय वायु सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु अविवाहित युवक एवं युवतियों से ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट अग्निपथवायु.सीडीएस.इन पर आमंत्रित किया गया है। अग्निवीर वायु भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम 31 जुलाई 2025 तक निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के वेबसाइट पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 2005 से 02 जनवरी 2009 के बीच हुआ हो। साथ ही 12वीं कक्षा न्यूनतम 50 अंको तथा अंग्रेजी विषय में 50 अंक के साथ उत्तीर्ण हो वे आवेदन कर सकते हैं।

बिजली दरों को ले कर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है : भारत सिंह सिसोदिया

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव द्वारा लगाए गए आरोपों पर भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव और कांग्रेस जनता को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी तकनीकी और आर्थिक कारणों से जरूरी थी, न कि किसी राजनीतिक मंशा से।श्री सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार को बिजली उत्पादन और वितरण लागत में भारी इजाफा झेलना पड़ रहा है। कोयले की कीमतें, ट्रांसमिशन लागत और रखरखाव खर्च में हुई बढ़ोतरी के चलते दरें समायोजित करना आवश्यक था। जब देश और दुनिया में ऊर्जा की लागत बढ़ रही है, तो छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रह सकता। कांग्रेस के समय सिर्फ दरें कम दिखाने के लिए बिजली कंपनियों को भारी कर्ज में डूबो दिया गया था। भाजपा सरकार उसी गड़बड़े से राज्य को बाहर निकाल रही है। उन्होंने टीएस सिंहदेव के कोयला हमारा, जमीन हमारी वाले बयान को भ्रामक बताया। सिसोदिया ने कहा कि अगर संसाधन राज्य के हैं, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भाटे में जाकर पूरी व्यवस्था ठप कर दें। कांग्रेस का मॉडल सिर्फ सत्बिडी और वोट बैंक की राजनीति है, जबकि भाजपा का मॉडल दीर्घकालिक विकास और जवाबदेही का है।



अभाविप ने 138 मेधावी छात्रों का किया सम्मान राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर दिया जोर

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) अम्बिकापुर इकाई द्वारा मंगलवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में 468 विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, जिसमें हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के 138 मेधावी विद्यार्थियों को उनके बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि, पुंज्य संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि युवाओं के समग्र



विकास और राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। मुख्य वक्ता प्रांत संगठन मंत्री महेश साकेत ने अभाविप को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बताते हुए कहा कि यह संस्था युवाओं में राष्ट्रप्रेम,

सामाजिक चेतना और नेतृत्व भावना का विकास करती है। प्रदेश सहमंत्री अनंत सोनी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का बोध कराना भी है। नगर मंत्री रोनी मिश्रा ने कार्यक्रम की सफलता में सहयोग देने वाले सभी

कार्यकर्ताओं,शिक्षकों, पालकों व प्रशासनिक सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अभाविप के समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत हैं। यह कार्यक्रम न सिर्फ छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने की भावना से भी जोड़ा।

अम्बिकापुर-राजपुर मार्ग स्थिति ककना के पास मंगलवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जखमी हो गया था। उसे

इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुनील दास पिता कलेश्वर दास उम्र 24 वर्ष कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बकना खुर्द का रहने वाला था। वह

मंगलवार को बरियों से काम कर बाइक से घर लौट रहा था। ककना के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। इससे वह गंभीर रूप से जखमी हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए थे।

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टरेट का घेराव किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आयोजित इस रैली में कर्मचारियों ने बरसते पानी में छाता ओढ़कर पैदल मार्च किया और नारेबाजी करते हुए कलेक्टरेट पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सविलियन,स्थायीकरण,समान कार्य के लिए समान वेतन,ग्रेड पे व्यवस्था लागू करना, पारदर्शी कार्य मूल्यांकन प्रणाली, स्थानांतरण नीति और कैशलेस चिकित्सा बीमा शामिल हैं। एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से वर्ष 2018 की मानव संसाधन नीति के तहत कार्यरत हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ हैं और कोविड काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी निरंतर सेवा दी,लेकिन



इसके बावजूद उन्हें संविदा के तहत अस्थिर भविष्य में कार्य करना पड़ रहा है। संघ की जिला अध्यक्ष शिल्पी राय ने मांग की कि शिक्षा विभाग की तर्ज पर एनएचएम कर्मचारियों का भी सविलियन किया जाए और जब तक स्थायीकरण की नीति नहीं बनती, तब तक नियमित भर्तियों में 50

प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों-मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा-की तरह छत्तीसगढ़ में भी एनएचएम कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे वेतन विसंगतियों को दूर किया जा सके। कर्मचारियों ने यह भी मांग की कि

कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत दुर्भावना का असर प्रदर्शन पर न पड़े। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, सवैतनिक चिकित्सा अवकाश, संतान पालन अवकाश तथा अर्जित अवकाश जैसी सुविधाएं भी नियमित कर्मियों की तरह दी जाएं। उन्होंने

पब्लिक हेल्थ कैडर के गठन की मांग करते हुए बताया कि इससे क्लिनिकल और मैनेजमेंट कैडर के एनएचएम कर्मियों को स्थायित्व मिलेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था में पेशेवर गुणवत्ता बढ़ेगी।

यह है प्रमुख मांगें... सविलियन व स्थायीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन व ग्रेड पे, कैशलेस चिकित्सा बीमा (10 लाख तक), पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली, सवैतनिक अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति,पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन, नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत पद आरक्षित सहित अन्य मांगों शामिल हैं। वहीं प्रदर्शन में जिलेभर से भारी संख्या में एनएचएम कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। यदि मांगों पूरी नहीं हुईं तो आगामी दिनों में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है।

होटल संचालक व गार्ड के साथ मारपीट करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

शहर के होटल संचालक व गार्ड के साथ की गई मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन पार्किंग की बात को लेकर आरोपियों ने होटल संचालक व गार्ड के साथ मारपीट किए थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। होटल संचालक केदारपुर निवासी दीपक जायसवाल ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि 8 जुलाई की शाम को विकास सोनी, चुम्मा शर्मा उर्फ दीपक शर्मा, विशाल मिंज,राहुल सिंह,अविनेन्द्र सिंह उर्फ सिम्पू,सिद्धार्थ त्रिपाठी, गोरा खान एवं अन्य लोग सेहत भोजनालय से खाना खाकर बाहर निकले,जो अपने वाहनों को प्रांथी के होटल के सामने बेतरतीब तरीके से खड़ी किये थे। होटल के गार्ड सूरज द्वारा उन्हे अपने वाहन को



सही तरीके से खड़ा करने के लिए बोल रहा था। इतने में सभी मिलकर गार्ड को गाली गलौज करने लगे, तब होटल संचालक दीपक द्वारा उक्त युवकों को गाली गलौज करने से मना करने पर उक्त युवकों ने हाथ मुक्के,तथा स्टील के रॉड, हॉकी स्टीक से गार्ड को मारने लगे तब दीपक जायसवाल व इसके चाचा सतीश जायसवाल बीच बचाव करने गये तो युवकों ने इनके साथ भी मारपीट की थी। दीपक जासवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी चुम्मा शर्मा उर्फ दीपक शर्मा पिता संतोष शर्मा उम्र 32 वर्ष

निवासी आईटीआई कॉलोनी कोर्ट के पीछे, विकास सोनी उर्फ भोला सोनी पिता दशरथ प्रसाद सोनी उम्र 27 वर्ष नगर निगम पानी टंकी के पास,अविनेन्द्र सिंह उर्फ सिम्पु पिता रोजश सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी बाबूपारा जेल रोड,विशाल मिंज आत्मज कुवर साय मिंज उम्र 37 वर्ष निवासी नावापारा चर्च के सामने थाना गांधीनगर, राहुल सिंह आत्मज स्व. सतेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी मिशन चौक, सिद्धार्थ त्रिपाठी उर्फ सिद्ध पिता धनंजय त्रिपाठी उम्र 32 वर्ष निवासी शिव मंदिर के नीचे गांधीनगर,गोरा खान

उर्फ मो. जावेद सिद्धकी पिता मजहर अली उम्र 44 वर्ष निवासी टावर गली मोमिनपुरा थाना अम्बिकापुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296,351(3),115(2), 3(5),191(2),191(3), 234,333 के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।पुलिस ने बताया कि आरोपी गोरा खान, विशाल मिंज एवं सिद्धार्थ त्रिपाठी के विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। मामले में अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार हैं, जिसकी पता तलाश की जा रही है।

साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल अकाउंट के दो और आरोपी गिरफ्तार

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी और अवैध सट्टा लेन-देन में प्रयुक्त म्यूल अकाउंट के दो खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कुछ राशि के बदले में अपने बैंक खाते खोलकर अन्य अपराधियों को सौंपे थे, जिनका उपयोग साइबर फ्रॉड और सट्टा के अवैध लेनदेन में किया गया। गांधीनगर थाना पुलिस ने विवेचन के दौरान आरोपियों रवि कुमार माझी और धीरज कुमार सिंह का पता लगाकर उन्हें हिरासत में लिया। पुछताछ में रवि कुमार माझी (पिता सांती राम माझी, उम्र 34 वर्ष, निवासी नेहरु वार्ड, सत्तीपारा)



और धीरज कुमार सिंह (पिता स्व. दिलीप सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी बीचपारा, फूंदरुड्डिरी) ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ रकम के बदले अपना खाता खुलवाकर अन्य आरोपियों को सौंपा था। इन खातों का उपयोग अवैध सट्टा और



साइबर ठगी की रकम के लेनदेन में किया गया। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों के खातों से साइबर फ्रॉड से प्राप्त धनराशि का लेनदेन किया गया है। मामला थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 397/25, धारा 317(4),

318(4), 61(2) बी.एन.एस. के तहत दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

मामले में शामिल अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप जायसवाल,साइबर सेल एएसआई अजीत मिश्रा,प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा,आरक्षक अरविंद उपाध्याय,ऋषभ सिंह, घनश्याम देवांगन, वीरेंद्र पैकरा,अनुज जायसवाल,जितेश साहू,मनीष सिंह, राहुल केकेकेन्द्र व अमनपुरी की सक्रिय भूमिका रही।

जिला पंचायत सदस्यों के तीन दिवसीय आधारभूत एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण की हुई शुरुआत

अम्बिकापुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के सभाकक्ष में बुधवार को जिला पंचायत सदस्यों के तीन दिवसीय आधारभूत एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। यह प्रशिक्षण 18 जुलाई 2025 तक जारी रहेगा। प्रशिक्षण की शुरुआत दीप प्रवलन कर किया गया। शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत सरगुजा के सदस्यों के साथ-साथ उपायुक्त सरगुजा श्री आर.के. खूटे, जिला



पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल, क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र सरगुजा के प्राचार्य श्री हरिशंकर

चौहान, उपसंचालक पीटीसी श्री मिथलेश पैकरा, उप संचालक पंचायत श्री यशपाल प्रेक्षा, संकाय सदस्य श्रीमती श्रद्धा मिश्रा एवं श्री उमेश प्रसाद सिंह उपस्थित थे।

सोख्ता गड़ड़ा निर्माण में जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज जल संरक्षण के दिशा में जनभागीदारी एवं प्रशासन का विशेष प्रयास

बलरामपुर 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

जल संरक्षण के उद्देश्य से जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान अंतर्गत लक्ष्य से अधिक 1 लाख 65 हजार 193 सोख्ता गड़ड़ों का निर्माण किया गया। जिसमें ग्रामीणों, महिलाओं, आमजनो ने सोख्ता गड़ड़ों निर्माण में जनसहभागीता दिखाते हुए जलसंरक्षण की दिशा में मिशाल पेश की जिसके तहत सोख्ता गड़ड़ा निर्माण में

जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड की स्टेट हेड श्रीमती सोनल शर्मा ने कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान जिला पंचायत सईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर व अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

ताली और थाली के माध्यम से किया गया सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन

कोरोना योद्धाओं का कर रही सरकार अपमान,भूल गई वादे...
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया आरोप

—संवाददाता—
सूरजपुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।

नियमितकरण,जॉब सुरक्षा,ग्रेड पे ,अनुकंपा नियुक्ति,मैडिकल बीमा,27 प्रतिशत वेतन वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत 16 हजार कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन आज सातवें दिन भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में आज सभी 33 जिला मुख्यालय में ताली और थाली रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपा,और कहा है कि, यदि उनकी मांगे जल्द ही नहीं पूरी की जाती हैं तो प्रदेश में एनएचएम के 16 हजार सविदा स्वास्थ्य कर्मचारी किसी



बड़े अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने को विवश हो सकते हैं जिस कारण प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में जो असुविधा जन्मदेर होगा। सूरजपुर के जिला अध्यक्ष बृजलाल पटेल ने बताया कि

जिले में 640 के करीब एन एच एम कर्मचारी कार्यरत हैं यह कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवा शतों में सुधार,नियमितकरण,अपनी नौकरी की सुरक्षा, समान काम समान वेतन, जैसी चाह लिए लगातार पिछली कई सरकारों के कार्यकाल में धरना प्रदर्शन आंदोलन अनुनय निवेदन ज्ञापन देते रहे हैं इस सरकार के कार्यकाल में भी मोदी की गारंटी के नाम से हमारी समस्याओं के समाधान का वादा किया गया है परंतु आज पर्यंत इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लगभग 100 से अधिक बार ज्ञापन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को दिया है इसके अलावा कई उच्च अधिकारियों से भी भेंट की गई है ,परंतु परिणाम शून्य ही रहा जिसके कारण 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक या प्रदर्शन चरणबद्ध रूप से जारी है। कर्मचारियों ने बताया कि, वह ताली और थाली करने पर आज इसलिए मजबूर हैं क्योंकि कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कोरोना वॉरियर का दर्जा देकर पूरे देश भर से हमारे लिए ताली और थाली बजवाई थी परंतु आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी हम कोरोना योद्धा जिनके लिए देशभर में तालियां थाली बजी,20 वर्षों से पीड़ित हैं जिसके कारण आज लाचार होकर अपने लिए ताली और थाली बजाने पर विवश हो चुके हैं । आंदोलन की कड़ी में 10 तारीख को सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया,11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया 12 से 15 तक काली पट्टी लगाकर कार्य किया गया एवं 16 जुलाई को जिला स्तरीय पर एक दिवसीय धरना रैली की गई जबकि 17 जुलाई को पूरे प्रदेश के यह कर्मचारी रायपुर में राजधानी धरना स्थल पर एकत्रित होकर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे ।

इस अवसर पर बृजलाल पटेल,तोपान सिंह दायमा,विवेक सदन नाविक,डॉ.अनुराग सिंह,संदीप नामदेव, लव सिंह मराबी सखन आयाम,श्रीमती कंचन जायसवाल, राजेश द्विवेदी,बृजेश कुशवाहा,कुलदीप पैकार,गिरजा मानिक पुरी,कुंवर प्रताप,रामकुमार सिदार, तोयात्मा रायल,कमलेश सोनी,उत्तरा कुमार,समय लाल,रविकरण सिंह, डॉ.कुलदीप दुबे,ओमप्रकाश राजवाड़े, अमित वर्मा,सरोज साहू,नंदकिशोर वर्मा एवं समस्त एनएचएम अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे

हराटिकरा के खेलों इंडिया सेंटर में फुटबॉल अस्मिता लीग का किया गया आयोजन

—संवाददाता—
सूरजपुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।
छ.ग. शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्देशित तथा कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के

मागदर्शन में खेलों इंडिया सेंटर हराटिकरा में अस्मिता सिटी लीग का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना व महिलाओं को प्रेरित करना और उभरती हुई प्रतिभाओं को बढ़ावा देना इस उद्देश्य से खेलों इंडिया सेंटर हराटिकरा में फुटबॉल अस्मिता सिटी लीग का आयोजन किया गया। जिसमें शिवपुर, उमेशपुर, खेलों इंडिया सेंटर हराटिकरा, खेलों इंडिया सेंटर अम्बिकापुर, एवं कोरिया अम्बर के कुल 05 टीमों ने इस आयोजन में भाग लिया, जिसमें विजेता शिवनगर उपविजेता खेलों इंडिया सेंटर हराटिकरा एवं तृतीय स्थान खेलों इंडिया सेंटर अम्बिकापुर का रहा, आयोजन में अतिथि के रूप में डीपी कलेक्टर सूरजपुर श्री सुनील

भारतीय वायु सेना अग्निपथ योजना अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती हेतु अधिसूचना जारी

—संवाददाता—
सूरजपुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।
भारतीय वायु सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती वर्ष 2026 हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। अग्निवीर वायु भर्ती हेतु अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल साइट <https://agnipathvayu.cdac.in> पर दिनांक 11 जुलाई को 11:00 बजे से 31 जुलाई को रात के 11:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

शा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवनंदनपुर में एससीवीटी व्यवसाय स्टेनो हिन्दी के लिए ऑनलाइन आवेदन पुनः आमंत्रित

—संवाददाता—
सूरजपुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।
शा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था शिवनंदनपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एससीवीटी व्यवसाय स्टेनो हिन्दी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई फिर से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 जुलाई 2025 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल वेबसाइट cgiti.admission.nic.in के माध्यम से ही किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025: प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई

—संवाददाता—
सूरजपुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्यभर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कराएं, जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निकाली रैली,सौपा ज्ञापन

—संवाददाता—
सूरजपुर, 16 जुलाई 2025 (घटती-घटना)।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज सूरजपुर में भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू करने के संबंध में ध्यानाकर्षण रैली निकाल ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 16 जुलाई को प्रदेशभर में एकजुट होकर सभी कर्मचारी-अधिकारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की गारंटी के अनुरूप सुविधाएं लागू करवाने और राज्य सरकार से लंबित मांगों के जल्द निराकरण की मांग को लेकर किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न पेंशनर्स संगठनों ने भी फेडरेशन के आंदोलन को पूर्ण समर्थन कर आंदोलन में शामिल हुए। फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ आर एस सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक ढंग से आयोजित किया गया। सूरजपुर के सुदूर अंचलों तक सभी कर्मचारी-अधिकारी रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद किये। फेडरेशन के सभी संगठनों, पदाधिकारियों व कर्मचारियों से इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाया। फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगें हैं। इनमें केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों व पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू किया जाए। डीए एरिसस की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। पुरानी पेंशन योजना हेतु नियुक्ति तिथि से गणना की बहाली पर गंभीर पहल हो । सहायक शिक्षकों व सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए।

तहसीलदार शंकरगढ़
जिला-वतरामपुर रामानुजगंज (छ0ग0)

मांमले की श्रेणी:- राजस्व
संदर्भ:- जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज
तहसील-शंकरगढ़ प.ह.न.-00014 शंकरगढ़
ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण
क्रमांक:-MIJ202425650503300019

ईशतहार

तहसील शंकरगढ़ के प.ह.न. 00014 के अंतर्गत ग्राम शंकरगढ़ के वर्तमान भूमिस्वामी बृन्दासिंह पिता/पति- पि. चन्द्रकासिंह पता-सा.अम्बिकापुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 41/3(2.0230) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता अविनाश पिता/पति-बृन्दा पता,अमित पिता/पति-बृन्दा पता के नाम पर पंजीयन/प्लॉट होने के उपरांत नामांतरण / अभिलेख दुरुस्ती / खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधो हस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचारधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 31/07/2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार शंकरगढ़ पर की जावेगी। उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इशतहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं / अधिवक्ता / आममुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08/07/2025 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार
आइ.सी.यादव

सील तहसील शंकरगढ़ बलरामपुर
रामानुजगंज (छ0ग0)

न्यायालय नजूल अधिवक्ता अम्बिकापुर
जिला सरगुजा छ0ग0

रा0प्र0क्र0./36-6/2024-25

ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदनकर्ता हर्षप्रत सिंह टुटेजा, गुप्तीत सिंह टुटेजा आरविन्द प्रताप सिंह, जाति सिक्ख,निवासी बाबूपाड़ा अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदवश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा अनावेदक रेखा सिंह पति दिनेश सिंह,जाति क्षत्रिय,निवासी देवनंदन नगर फेस-2,सोपत रोड,चांटीडीह बालाजी प्रोविजन के पास, बिलासपुर, तह. बिलासपुर छ0ग0, पावर होल्डर दिनेश कुमार सिंह पिता स्व. जगदीश सिंह, जाति क्षत्रिय, निवासी देवनंदन नगर फेस-2, सोपत रोड, चांटीडीह बालाजी प्रोविजन के पास, बिलासपुर, तह. बिलासपुर छ0ग0 के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 09 मोहल्ला बाबूपाड़ा स्थित नजूल प्लॉट नं. 3504/3 में से रकबा 1742.4 वर्गमी0 भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त क्रयशुदा भूमि के नजूल अभिलेख में आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं का नाम दर्ज करने हेतु पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति, मयदस्तावेज सहित आवेदन पत्र,अन्तर्गत धारा 109, 110 छग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 08/08/2025 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 11/ 07 / 2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,सरगुजा(छ0ग0)

सील

न्यायालय नजूल अधिवक्ता अम्बिकापुर
जिला सरगुजा छ0ग0

रा0प्र0क्र0./36-6/2024-25

ईशतहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदनकर्ता हर्षप्रत सिंह टुटेजा, गुप्तीत सिंह टुटेजा आ. रविन्द प्रताप सिंह, जाति सिक्ख, निवासी बाबूपाड़ा अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदवश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदनकर्ता द्वारा अनावेदक रेखा सिंह पति दिनेश सिंह, जाति क्षत्रिय, निवासी देवनंदन नगर फेस-2, सोपत रोड, चांटीडीह बालाजी प्रोविजन के पास, बिलासपुर, तह. बिलासपुर छ0ग0 के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 09 मोहल्ला बाबूपाड़ा स्थित नजूल प्लॉट नं. 3503 रकबा 2178 वर्गफीट एवं प्लॉट नं. 3504/4 में से रकबा 7840.8 वर्गमी0 कुल 10018.8 वर्गफीट भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त क्रयशुदा भूमि के नजूल अभिलेख में आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं का नाम दर्ज करने हेतु पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति, मयदस्तावेज सहित आवेदन पत्र, अन्तर्गत धारा 109, 110 छग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 08/08/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 11/ 07 / 2025 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,सरगुजा(छ0ग0)

सील

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के
न्यायालया क्रमांक:
202507020700015

विषय:- ब-121मांमले की श्रेणी:- राजस्व
सन्:- 2024-2025

हराटिकरा प.ह.न. 00024 [(ह0)]
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार-रोहित कुमार मिश्रा,
अनावेदक पक्षकार -छ0ग0 शासन,

ईशतहार

आवेदक रोहित कुमार मिश्रा आ0 अतुल कुमार मिश्रा व अन्य, निवासी ग्राम हराटिकरा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदनकर्ता के स्वामित्व एवं अधिपत्य की ग्राम हराटिकरा स्थित खसरा नंबर 502/52, 502/50, 502/51 रकबा क्रमशः 0.047, 0.048, 0.048 हे0 भूमि का बंटवारा हो चुका है, किन्तु उक्त भूमि का नक्शा बंटवारा अनुसार नहीं कटा है, जिस कारण नक्शा में त्रुटि हो गया है। आवेदनकर्ता के द्वारा आवेदित भूमि के नक्शा में सुधार हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 08.08.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने नहीं किया जावेगा। अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08/07/2025 को जारी किया जाता है।

श्रीमान/श्रीमती
मान्यवर,
बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूज्य माता जसमती देवी जी का स्वर्गवास दिनांक 06.07.2025 दिन रविवार को हो गया जिनकी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु - निम्न कार्यक्रम है जिसमें आपकी उपस्थिति प्राथमिक है

कार्यक्रम
17.07.2025,दिन
गुरुवार दशगात्र
20.07.2025,दिन
रविवार ब्राम्हणभोज

शोकाकुल
प्रदीप कश्यप
धर्मजीत कश्यप
बस स्टैंड प्रतापपुर
वार्ड नं04

CMYK

प्रदेश की संक्षिप्त खबरें

नेता प्रतिपक्ष महंत ने सीएम
साय को दिया धन्यवाद



सत्ता पक्ष ने तालियां बजाकर किया स्वागत, रायपुर, 16 जुलाई 2025(ए)। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बुधवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पिछले 25 वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए राजनीतिक शिष्टाचार का नया अध्याय रच दिया। आमतौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और स्थान प्रस्ताव खारिज होने पर वाकआउट की घटनाएं आम होती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के रुख की सराहना भी की।

जेल से छूटकर 70 साल
की बुजुर्ग से किया रेप



रायपुर में बेटे ने 5 दिन-तक की दरिदगी, 5
वर्षीय बच्ची से कर चुका है दुष्कर्म

रायपुर, 16 जुलाई 2025(ए)। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेटा 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 4-5 दिनों तक रेप करता रहा। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो वृद्ध ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले वो 5 साल की बच्ची से भी दुष्कर्म कर चुका है। घटना मामले आरंभ थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी 42 साल का है। जेल से छूटने के बाद वो बुजुर्ग महिला से छेड़खानी करने लगा। उसने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कुछ दिन पहले ही चार से पांच दिनों तक लगातार रेप किया। 15 जुलाई को पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत की।

अब सरकारी स्कूलों में भी
होगी पालक-शिक्षक बैठक

रायपुर, 16 जुलाई 2025(ए)। अब सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर पालक-शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर नियमित संवाद स्थापित किया जा सके। पहली बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी, जिसमें



पालकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों, कमजोरियों और समग्र विकास की जानकारी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों और पालकों के बीच समन्वय को सशक्त बनाना है, जिससे छात्र शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और उन्हें सहयोगपूर्ण घर का माहौल मिल सके। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को साकार करने और ड्रॉपआउट की समस्या को रोकने में पालकों की सक्रिय भूमिका जरूरी है।

साइबर ठगी मामले पर विधानसभा में हंगामा

साइबर ठगी पर विधायक सुनील सोनी के सवाल पर घिरे गृहमंत्री विजय शर्मा, 1 साल में 1 हजार 301 मामले...



मेकाहारा में बंद मशीनों के
बदले नई मशीन खरीदी
जाएगी :स्वास्थ्य मंत्री
जायसवाल

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मेकाहारा में कुल 161 मशीन उपलब्ध हैं जिसमें से 111 मशीन चालू है तथा 50 मशीनें बंद हैं। इनमें से 49 बंद मशीनों के बदले नई मशीन की खरीदी की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस सदस्य श्रीमती शेषराज हरवंश द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति में मेकाहारा राज्य सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर हार्ट तथा कैन्सर जैसी गंभीर बीमारियों की परीक्षण के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मशीनें बंद होने के कारण लोग वापस जाते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह मशीन कांग्रेस शासनकाल में खरीदी गई थी। भाजपा के अजय चन्द्राकर ने कहा कि ये मशीन खरीदी का आर्डर दिया था लेकिन सत्ता बदल गई। कांग्रेस सदस्य शेषराज हंसराज ने कहा कि मशीनें खराब होने के कारण हजारों मरीज वापस जाते हैं।



चुनौती देकर खुद भाग खड़े हुए भूपेश बघेल, गृहमंत्री विजय शर्मा का आरोप

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की भी नाराजगी देखने को मिली। दरअसल पूर्व सीएम और कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास को लेकर सवाल पूछे थे। वहीं आज वह सदन से नदारद रहे। इस पर संबंधित विभाग के मंत्री नाराज हुए। मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पीएम आवास पर भूपेश बघेल ने चुनौती उठे दी थी। कहीं और किसी भी मंच पर बातचीत कर लेने की बात कही थी। आज सदन में विषय लगा था, यह बहुत अच्छा मौका था। मैं पूरी तैयारी के साथ सदन में आया था। लेकिन भूपेश बघेल सदन से गायब थे। विजय शर्मा ने कहा कि, यह बहिर्गमन नहीं था, यह कांग्रेस का पलायन था।

विधानसभा में नकल प्रकरण का मामला गुंजा

विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। बिलासपुर में पिछले दिनों लोनिवि भर्ती की परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराये जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था। इसके बाद से ही कांग्रेस सत्तादल भाजपा पर हमलावर है। वहीं आज इस नकल प्रकरण की गूँज विधानसभा में भी सुनाई दी। प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख विधायक दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि, क्या नकल गिरोह को भाजपा की सरकार संरक्षण दे रही है? बीजेपी के 15 साल की सरकार में बस्तर, बिलासपुर में फर्जी परीक्षाएं आयोजित हुईं। अगर संरक्षण नहीं तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि, सरकार में आने से पहले भाजपा ने यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षा करने का दावा किया था तो क्या यही यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा है। सदन में बिजली के दाम में बढ़ोतरी पर स्थान प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि के गई है, आपूर्ति में गुणवत्ता है। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऊर्जा सुधारों को जनसमर्थन मिल रहा है।

विजय शर्मा पर महंत की टिप्पणी से सदन में मचा बवाल

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्ति की स्थिति की जानकारी के बारे में नेता प्रतिपक्ष चरणदास द्वारा पूछे गये प्रश्न के दौरान उन्होंने पंचायत एवं गृहमंत्री विजय शर्मा पर तंज कस दिया। जिसको लेकर सदन में विवाद हो गया। अध्यक्ष रमन सिंह ने पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए इस टिप्पणी को विलोपित करने का निर्देश दिया। जिसके पश्चात सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य शांत हुए।

प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने आईटी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी-गृहमंत्री

प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छ्पा सरकार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक कुल 107 प्रकरणों में 3.69 करोड़ की राशि पीड़ितों को दिलाई गई है। राज्य में शीघ्र आईटी पेशेवर साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।

जल्द होगी साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति: विजय शर्मा

विधायक सुनील सोनी ने कहा- साइबर थाने में साइबर एक्सपर्ट नहीं हैं, आईजी रैंक के अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। जिस पर गृहमंत्री



विजय शर्मा ने कहा- सीएम के हाथों में साइबर थाने का उद्घाटन हुआ है। साइबर थाने में हाईटेक उपकरण है। साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति जल्द होगा। हर जिले में साइबर के विवेचक पदस्थ हैं। विधायक सुनील सोनी ने कहा- जिलों के थाने साइबर क्राइम रोकने क्या सक्षम है। जिस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- साइबर थानों को जांच के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। अप्सरों को डेपुटेशन पर लेकर थानों में पदस्थ किया जा रहा है। 9 जिलों में हाईटेक साइबर थाने बनाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं सुनील सोनी ने पूछा क्या साइबर क्राइम में बैंक के भी संलिप्त है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, 7 बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। सभी पर एफआईआर दर्ज की गई।

सदन में रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार की गूँज, विपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

विधानसभा में मंगलवार को रेडी टू ईट का मामला विपक्ष ने उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। इसके ठेके में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग स्वीकार नहीं करने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ध्यानकर्षण सूचना के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सरकार ने रेडी टू ईट योजना के संचालन में भारी गड़बड़ी की है। अपात्र महिला स्वसहायता समूहों को भी ठेका दे दिया गया है जबकि पात्र समूहों को बाहर कर दिया गया है। इसके चयन समिति में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग नेता प्रतिपक्ष ने की। कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने भी इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डिफाल्टर महिला स्वसहायता समूहों को ठेका देने की जानकारी सदन में दी।

विद्युत दरों को बढ़ाने कांग्रेस ने किया विरोध

विधानसभा के मानसून सत्र में आज शून्य काल में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बिजली की बढ़ती दरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विद्युत मंडल लाइन लाश तथा स्थापना व्यय को बढ़ाते जा रहा है। इसका बोझ गरीब किसानों पर पड़ रहा है। सत्र में कांग्रेस के सदस्यों ने विद्युत दरों में बढ़ोतरी



को जनता के साथ अन्याय बताया और कांग्रेस कार्यकाल में इसे एक बार बढ़ाने का ही काम किया गया जबकि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में दो बार वृद्धि कर दी है। स्थान प्रस्ताव में सदस्यों का वक्तव्य सुनकर अध्यक्ष रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया कि वे अपना पक्ष रखें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विद्युत दरों में न्यूनतम वृद्धि की गई है। कांग्रेस के सदस्यों के आरोप को जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत नियामक द्वारा वर्ष 2025-26 में विद्युत हेतु घोषित बिजली टैरिफ में 1.89 की वृद्धि की गई जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान पर संतोष जाहिर करते हुए धन्यवाद प्रेषित किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षीय सदस्यों का जवाब देते हुए कहा कि बिजली दरों न्यूनतम वृद्धि की गई है।

किसानों को नहीं देना होगा बढ़ा बिजली बिल,सरकार देगी सब्सिडी



रायपुर, 16 जुलाई 2025 (ए)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली के बढ़े दामों को मामूली बताया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिल के दाम बढ़ाए हैं। इस पर सीएम ने कहा

कि, वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ में मात्र 1.89% की वृद्धि की गई है, ये जो विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। साथ कहा कि, किसानों को सब्सिडी मिल रही ऐसे में किसानों पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा।

नए और पुराने दर में कितना बदलाव

सौर ऊर्जा की ओर एक कदम- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी सब्सिडी मिल रही है। 3 किलोवाट तक के संयंत्रों पर ₹78 हजार तक केंद्र सरकार से अतिरिक्त 2 किलोवाट तक के संयंत्रों पर ₹30 हजार तक राज्य शासन से अनुदान दिया जाएगा। यह योजना छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल है।

बिजली बिल पर सीएम ने क्या कहा:

हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ष पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50

पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इसका भी सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है।
स्टील इंडस्ट्री की दरों में कटौती:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार

ने उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए मिनी स्टील, रोलिंग मिल और फेरो एलॉय जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों की दरों में कटौती की है। यह निर्णय उद्योगों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है।

वर्तमान टैरिफ में केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान

इसके तहत ट्रांसमिशन कंपनी के लिए ₹2433 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए ₹3977 करोड़ और जनरेशन कंपनी के लिए ₹2992 करोड़ का प्रावधान है। कोरेखा में 1320 मेगावाट के प्लांट की स्थापना का काम भी शुरू हो चुका है, जिसकी लागत ₹15,800 करोड़ है। इससे छत्तीसगढ़ भविष्य में ऊर्जा-सुरक्षा राज्य बनेगा।

रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द छत्तीसगढ़ में मेडिकल

की 150 सीटें होंगी कम

रायपुर, 16 जुलाई 2025 (ए)। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रिश्तत कांड में फंसे रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज की 150 सीटें कम हो जाएंगी। अब तक प्रदेश में 700 मेडिकल सीट थीं, जो घटकर 550 हो जाएंगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सिर्फ



शासकीय मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमिशन ने नए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता दी है। जिसके बाद प्रदेश के 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज की करीब 1,430 सीटों पर एडमिशन दे पाएगी। सभी कॉलेजों की 4 महीने बाद फिर से समीक्षा की जाएगी किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज की सीटों में इजाफा नहीं किया है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की ओर से कहा गया है कि, किसी मेडिकल कॉलेज ने सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन भी नहीं किया था।

रायपुर में दित्यांगों को घसीटकर ले गई पुलिस

बस-स्टैंड से उठाकर गाड़ी में डाला तृता धरनास्थल पर छोड़ा

रायपुर, 16 जुलाई 2025 (ए)। रायपुर में बस स्टैंड के पास बैठे दिव्यांग संच के लोगों को पुलिस ने बलपूर्वक उठाया और गाड़ी में डालकर नवा रायपुर स्थित तृता धरनास्थल ले गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। जिसमें पुलिस महिलाओं और पुरुषों को घसीटकर हटाते नजर आ रही है।

महिला दिव्यांगों के साथ बदसलूकी का आरोप

विधानसभा घेराव से पहले वायरल हुए वीडियो में पुलिस महिला दिव्यांगों को घसीटते और बदसलूकी करते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर निकले थे, लेकिन पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही है। दिव्यांग संच के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन किया है और सरकार



के आधासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन अब तक मांगें पूरी नहीं होने पर आज सभी दिव्यांग विधानसभा का घेराव करने रायपुर पहुंच रहे हैं।
148 से अधिक अधिकारी कर रहे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी
विधानसभा घेराव से पहले

दिव्यांग संच के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चर्चनित 7 डिग्री कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 पशु चिकित्सक सहित कुल 148 अधिकारियों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की है।